



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 5, 2012/आश्विन 13, 1934

No. 229]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2012/ASVINA 13, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2012

**विषय :** यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पालीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) सस्पेंशन ग्रेड रेजिन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

सं. 14/1012/2012-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) के अनुसार यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पालीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) सस्पेंशन ग्रेड रेजिन (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष मैसर्स डी सी डब्ल्यू लिमिटेड (डी सी डब्ल्यू), केम्प्लास्ट सन्मार लिमिटेड (केम्प्लास्ट), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) और डी सी एम श्रीराम कन्सालिडेटेड लिमिटेड (डी सी एम) ने एक आवेदन पत्र दायर किया है ।

2. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित एचएस कोड नहीं है और इनके आयात को 3904 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न एचएस कोडों के अंतर्गत, क्लीयर किया जाता है। सीमाशुल्क वगीकरण केवल संकेतक है और यह इस जाँच के दायरे के अंतर्गत किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

#### घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह याचिका डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (डीसीडब्ल्यू), चेम्प्लास्ट सन्मार लिमिटेड (चेम्प्लास्ट), रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रिलायन्स) तथा डीसीएम श्रीराम कन्सालीडेटेड लिमिटेड (डीसीएम) द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। मैसर्स फिनोलेक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जो संबद्ध वस्तु का भारत में अन्य ज्ञात एकमात्र उत्पादक है, ने इस याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि डीसीएम श्रीराम कन्सालीडेटेड लिमिटेड को छोड़कर किसी भी अन्य याचिकाकर्ता कम्पनी ने जाँच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता कंपनी, जो संबद्ध वस्तु का आयात करती है, पाटन का लाभ उठाने के उद्देश्य से आयात नहीं करती है। इन याचिकाकर्ता कम्पनियों का थ्रस्ट आयातों की ओर नहीं है। कम्पनी का थ्रस्ट अपना उत्पाद ही है।

4. प्राधिकारी ने मामले की जाँच की और पाया कि याचिकाकर्ता कंपनियों में से कोई भी कंपनी समरूप व्यापारी नहीं है और उन्होंने पाटन से लाभ उठाने के लिए आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता का मुख्य ध्यान उत्पादक और संबद्ध वस्तु के उत्पादक का बना रहा। प्राधिकारी ने मामले की जाँच की और पाया कि याचिकाकर्ता कंपनियों में से कोई भी कंपनी समरूप व्यापारी नहीं है और उन्होंने पाटन से लाभ उठाने के लिए आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता का मुख्य ध्यान उत्पादक और संबद्ध वस्तु के उत्पादक का बना रहा। प्राधिकारी ने विचार किया है कि कोई भी याचिकाकर्ता कम्पनी नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद का आयातक नहीं है। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी की जाँच करने के पश्चात यह निश्चय किया है कि याचिकाकर्ता कम्पनियाँ नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और यह याचिका नियम 5 के अंतर्गत बने नियमों में दी गई स्थिति की प्रक्रिया को संतुष्ट करती है।

#### समान वस्तु

5. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य तथा उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण तथा विपणन और टैरिफ वगीकरणों के रूप

में समान है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है तथा उपभोक्ता इनका अंतर्बदल का प्रयोग कर सकते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को इस समीक्षा जांच के उद्देश्य के लिए संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के "समान वस्तु" के रूप में माना गया है।

#### संबद्ध देश

6. वर्तमान आवेदन यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के आरोप के बारे में दायर किया गया है।

#### सामान्य मूल्य

7. याचिकाकर्ताओं ने यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको और थाइलैंड में विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए हरीमन केम्सल्ट रिपोर्ट में उद्धृत कीमतों का उल्लेख किया है। यूरोपियन यूनियन के लिए याचिकाकर्ता ने बेनिलक्स (बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्जमबर्ग), फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यू. के. के लिए उद्धृत कीमत पर विचार किया है।

8. याचिकाकर्ता ने वी सी एम की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, परिवर्तन लागत अनुमानों और उपरिशीर्ष लागत पर विचार करते हुए विदेशी उत्पादकों की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। संबद्ध क्षेत्र/भू-भाग में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है।

#### निर्यात कीमत

9. निर्यात कीमत का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सूचना सेवा (आई बी आई एस) द्वारा प्रदान कराए गए संबद्ध देशों से सौदावार आयात आंकड़ों पर आधारित भारित औसत कीमत के रूप में किया गया था। इस कीमत समायोजन का दावा समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और कीमशन के आधार पर निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए किया गया था। समयावधि के साथ कीमतों में भारी भिन्नता को देखते हुए याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित जांच अवधि के प्रत्येक माह के लिए पृथक निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

#### पाटन मार्जिन

10. समयावधि के अंदर भारी कीमत भिन्नता के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं ने जांच अवधि के प्रत्येक माह के लिए पृथक कीमत मार्जिन का निर्धारण किया है।

11. याचिकाकर्ताओं ने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि संबद्ध वस्तु का संबद्ध देशों भू-भाग में सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत की तुलना में अत्यधिक उच्च है, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहा, जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराता है।

#### क्षति एवं कारणात्मक संबंध

12. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को विपरीत कीमत प्रभाव के रूप में वास्तविक क्षति हुई है जो कीमत में कटौती कीमत हास और लाभदायकता, लगाई गई पूंजी पर आय और घरेलू उद्योग के नकदी लाभ में कमी से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों भू-भागों से पाटित आयातों के कारण सतत वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों/भू-भागों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सतत "क्षति" के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराते हैं।

#### पाटनरोधी जांच की शुरुआत

13. उपर्युक्त पैराग्राफों में दी गई जानकारी के आधार पर प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और क्षति एवं कथित पाटन के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराते हैं। प्राधिकारी कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत एतद्वारा कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी डिग्री तथा प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो यदि अधिरोपित की जाती है तो घरेलू उद्योग की क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

#### जांच अवधि

14. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 (12 माह) है। तथापि क्षति विश्लेषण के लिए 1 अप्रैल, 2008 से जांच की अवधि की समाप्ति तक समय अर्थात् 2008-09, 2009-10, 2010-11 और जांचावधि शामिल होगी।

#### सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देशों में जात निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उनके दूतावास के जरिए, भारत में इस उत्पाद से संबंधित जात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है :

भारत सरकार  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
कमरा नं. 243, उद्योग भवन  
नई दिल्ली-110107

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है।

**समय-सीमा**

17. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुँच जाना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी-अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा नहीं जारी रखने की आवश्यकता के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ इस जांच के शुरू होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

19. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक सूची पृष्ठ सं. इत्यादि सहित) तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक सूची पृष्ठ सं. इत्यादि सहित)। प्रस्तुत की गई प्रत्येक सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिह्नित होना अनिवार्य है।

3803 GF/12-2

20. किसी चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को आगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का अवलोकन करने की अनुमति देने का अधिकार होगा। गोपनीय तथा अगोपनीय दोनों रूपांतरों की दो-दो प्रतियाँ अवश्यक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

21. जिस सूचना के लिए गोपनीयता का दावा किया गया हो; उस सूचना के प्रदाता द्वारा प्रस्तुत सूचना के साथ समुचित कारणों सहित इस आशय का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है तथा/अथवा ऐसी सूचना का साराँश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

22. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए या रिक्त छोड़ दिया जाए/संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय साराँश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।

23. प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच पर गोपनीयता हेतु निवेदन को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु निवेदन प्राधिकृत नहीं है अथवा सूचना प्रदायक या तो सूचना सार्वजनिक करने को अनिच्छुक है या सामान्य अथवा संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत नहीं कर रहा है, तो वे इस तरह की सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

24. सार्थक अगोपनीय रूपान्तर के बिना अथवा गोपनीयता की माँग के लिए उचित कारण का ब्यौरा दिए बिना किसी तरह का निवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने की स्थिति में तथा इसे स्वीकार करते हुए, इस तरह की सूचना प्रदान करने वाली पार्टी के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उसे किसी अन्य पार्टी के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

#### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

#### असहयोग

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th October, 2012

**Subject : Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of Polyvinyl Chloride (PVC) Suspension Grade Resin from European Union and Mexico.**

**No. 14/1012/2012-DGAD.**—M/s. DCW Limited (DCW), Chemplast Sanmar Limited (Chemplast), Reliance Industries Ltd. (RIL) and DCM Shriram Consolidated Ltd. (DCM), have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the petitioners or applicants) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping investigations concerning imports of Polyvinyl Chloride (PVC) grade Suspension Resin (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from European Union and Mexico (hereinafter also referred to as the subject countries).

**Product under consideration**

1. The Product under consideration in the present investigation is homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade), where various polymer chains are not linked to each other, falling under customs classification no. 3904, known as PVC suspension resin. The product under consideration excludes specialty PVC suspension resins such as cross-linked PVC, chlorinated PVC (CPVC), vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAc), PVC paste resin and PVC blending resin. The product under consideration has been referred to as "Poly Vinyl Chloride (PVC) Resin Suspension Grade" or "PVC Suspension Resin" or "the subject goods").
2. The petitioners have submitted that the product under consideration does not have dedicated HS Code and the imports are cleared under different HS Codes falling under 3904. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

**Domestic Industry & Standing**

3. The petition has been jointly filed by DCW Limited (DCW), Chemplast Sanmar Limited (Chemplast), Reliance Industries Ltd (Reliance) and DCM Shriram Consolidated Ltd. (DCM). M/s Finolex Industries Limited, the sole other known producer of the subject product in India has supported the petition. The petitioners have stated that none of the petitioner companies except DCM Shriram Consolidated Ltd have imported the product under consideration during period of investigation. Further they have submitted that petitioner company who is importing the subject goods is not resorting to imports in order to benefit from dumping. Thrust of this petitioner company has not turned to imports. The company's thrust continues to be on own production.
4. The Authority has examined the matter and holds that none of the Petitioner companies are a trader per se and have not resorted to imports in order to take advantage of dumping. The focus of the petitioner companies continues to be that of a producer of the subject goods. The Authority after examining the information on record determines that the applicant companies constitute domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules *supra*.

**Like Articles**

5. The Petitioners have claimed that the product produced by them is a like article to the product imported from the subject countries in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable, and consumers use the two interchangeably. Subject goods produced by the petitioners are being treated as 'like article' to the goods being imported from the subject countries for the purpose of the present investigation.

**Subject Countries**

6. The present application has been filed in respect of alleged dumping of the product under consideration from European Union and Mexico (hereinafter referred to as subject countries).

**Normal value**

7. The petitioners have for the purpose of determining normal value for European Union and Mexico referred to the prices quoted in the Harriman Chemsult report. For European Union, the petitioners have considered the price quoted for Benelux (Belgium,



Netherland and Luxemburg), France, Germany, Italy, Spain and UK. Petitioners have determined month-wise normal value by considering the average of the highest and the lowest price given in the report. Further, the petitioners have claimed that the prices in some of the months of the investigation period were significantly below the cost of production and have additionally determined normal value considering cost of production for those months where the sales are claimed to be below estimates of cost of production. The selling price of the product during the relevant months have been compared with the estimates of cost of production for those months.

8. The petitioners have also determined normal value on the basis of estimates of cost of production of the foreign producers by considering international price of VCM, estimates of the conversion cost and overhead costs. There is sufficient prima facie evidence of normal value of the subject goods in the subject countries/territory.

#### **Export Price**

9. The export price has been determined as the weighted average import price from subject countries based on the transaction wise import data provided by the International Business Information Services (IBIS). Price adjustments have been claimed on account of sea freight, marine insurance, port expenses, inland freight, bank charges and commission to arrive at the net export price. In view of significant variation in the prices with time period, the petitioners have determined separate export price for each of the months of the proposed investigation period.

#### **Dumping Margin**

10. In view of the significant variation in the prices over the time period, the petitioners have determined separate dumping margin for each month of the investigation period.
11. Petitioners have provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries/territory are significantly higher than the net export prices, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.

#### **Injury and Causal Link**

12. The petitioners have claimed that domestic industry has suffered material injury by way of adverse price effects as evidenced by price undercutting and price suppression leading to deterioration in profits to negative levels, decline in return on capital employed and cash profits, etc. . The petitioners have claimed that the material injury has been caused due to the dumped imports from the subject countries. The Authority considers that there is sufficient prima facie evidence of 'injury' caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries/territory to justify initiation of an anti-dumping investigation.

**Initiation of Anti Dumping Investigations**

13. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, holds that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove injury to the domestic industry.

**Period Of Investigation (POI)**

14. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2011 to 31<sup>st</sup> March 2012 (12 months). However, the period for injury examination would cover periods from 1<sup>st</sup> April 2008 to the end of the POI i.e. 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12(POI).

**Submission of Information:**

15. The known exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India  
Ministry of Commerce and Industry  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Department of Commerce  
Room No.243, Udyog Bhawan,  
New Delhi-110107.

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**Time Limit:**

17. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is

incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**Submission of information on confidential basis.**

19. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
20. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
21. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of public file:**

25. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

26. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority